



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13, 2001/आश्विन 21, 1923

No. 762]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 2001/ASVINA 21, 1923

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2001

का.आ. 1036(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किए गए निम्नलिखित आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री सुब्रमणियन स्वामी, अध्यक्ष जनता पार्टी ने श्री टी.टी.वी. दिनाकरन, लोक सभा के आसीन सदस्य की, उस सदन का सदस्य बने रहने से, निरर्हता के लिए तारीख 23.3.2001 को एक याचिका प्रस्तुत की थी जो उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन प्राधिकारियों के समक्ष कुछ कार्यवाहियों में स्वयं को अनिवासी भारतीय घोषित करने के कारण, सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्रास्थिति धारण करने के लिए, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम की विधियों के अधीन, जिनमें किसी निदेशक के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित उपबंध हैं और जो उनकी विधियों के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति का उपबंध करती हैं, रजिस्ट्रीकृत एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, डिप्पर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सोज और बेंजन ट्री का निदेशक होने के कारण और इस प्रकार सिंगापुर तथा यूनाइटेड किंगडम की विधियों द्वारा आबद्ध किए जाने के कारण, जो उसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार करना है और उसके द्वारा अपने को अनिवासी भारतीय घोषित करने के भारत में किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराए जाने के कारण थी ।

और राष्ट्रपति ने इस प्रश्न पर कि कि क्या श्री टी.टी.वी. दिनाकरन निरहता से ग्रस्त हो गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी ।

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध देखिए) दी है कि सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री टी.टी.वी. दिनाकरन की अभिकथित निरहता का प्रश्न, कदाचित, निर्वाचन पूर्व निरहता का मामला होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन न तो राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जा सकता है और न ही उनके द्वारा उसका विनिश्चय किया जा सकता है । परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग की ऐसी अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरहता के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । श्री टी.टी.वी. दिनाकरन के तमिलनाडु में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रश्न, जिससे कि वह निर्वाचन लड़ सकें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 84(ग) के अधीन एक अर्हता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन इसे राष्ट्रपति के समक्ष भी उठाया नहीं जा सकता है या उनके द्वारा इसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता है । अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार, राष्ट्रपति के समक्ष घलाए जाने योग्य नहीं है ।

अतः, अब, मैं, के.आर. नारायणन, भारत का राष्ट्रपति, इसके द्वारा यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री सुब्रह्माणियन स्वामी, अध्यक्ष, जनता पार्टी की याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और इसलिए, नामंजूर की जाती है ।

राष्ट्रपति ” ।

19 सितम्बर, 2001

उपाबंध**गणपूर्ति :**

माननीय श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति
निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री जे.एम. लिंगदोह
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री बी.बी. टंडन
निर्वाचन आयुक्त

2001 का निर्देश मामला संख्यांक 1

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : संसद् (लोक सभा) के आसीन सदस्य श्री टी.टी.वी. दिनाकरन की अभिकथित निरर्हता ।

निम्नलिखित के मामले में :-

श्री सुब्रमणियन स्वामी,
अध्यक्ष जनता पार्टी,
ए-77, निजामुद्दीन (पूर्वी)
नई दिल्ली - 110013 ।

याची

बनाम

श्री टी.टी.वी. दिनाकरन,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
पुत्र श्री विवेकानंदन,
24वीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर,
अड्यार,
चेन्नई-600020.

प्रत्यर्थी

राय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन, भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त इस निर्देश में, जो तारीख 6.6.2001 का है, इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या लोक सभा के आसीन सदस्य श्री टी.टी.वी. दिनाकरन, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन, उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. उपर्युक्त प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उपर्युक्त याची द्वारा तारीख 23.3.2001 को भारत के राष्ट्रपति को दी गई एक याचिका में उद्भूत हुआ था। उक्त याचिका में, याची ने यह अभिकथन किया था कि श्री टी.टी.वी. दिनाकरन, जिसने तमिलनाडु में 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से, जिसे याचिका में गलती से 75 - पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में उल्लिखित किया गया था, सितंबर, 1999 में हुए लोक सभा निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ा था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरर्हता उपाप्त करने के कारण, लोक सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए थे।

3. याची ने यह अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी, श्री टी.टी.वी. दिनाकरन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अधीन प्राधिकारियों के समक्ष कतिपय कार्यवाहियों में स्वयं को अनिवासी भारतीय घोषित किया है और यह कि उसने सिंगापुर सरकार के पास दस लाख डालर की रकम जमा करके सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्राप्ति प्राप्त कर ली है और वह वहां एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर नामक एक कंपनी का निदेशक भी बन गया और उसने अपना स्थायी आवासीय पता 37, जालान टेल्लटी, सिंगापुर दिया। याची ने आगे यह दलील दी कि उपरोक्त आशय के संबंध में आक्षेप, 1999 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा के समय पर 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के समक्ष भी किए गए थे किन्तु रिटर्निंग आफिसर ने इस प्रकार किए गए आक्षेपों को नामंजूर कर दिया था और प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र को विधिमाम्य रूप में स्वीकार कर लिया था।

4. याची ने आगे यह अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी यू.के. की विधियों के अधीन निगमित कुछ अन्य विदेशी कंपनियों जैसे कि डिप्पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सज और बेंजन ट्री, का भी निदेशक था। याची ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी, सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्राप्ति धारण करने के कारण और सिंगापुर तथा यू.के. की विधियों, जिनमें निदेशक के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित उपबंध हैं और उनकी विधियों के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्तियों के भी उपबंध हैं, के अधीन रजिस्ट्रीकृत एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, डिप्पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सज और बेंजन ट्री का निदेशक होने के कारण सिंगापुर और यू.के. की विधियों द्वारा आबद्ध है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 102(1) (घ) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए हैं, जो उसे संसद् की सदस्यता से निरर्हता के लिए दायी बनाती है। उपरोक्त प्रकथनों और दलीलों के समर्थन में याची ने अपनी याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की जेरोक्स प्रतियां प्रस्तुत की हैं :-

- (i) तारीख 2.4.1994 को निगमित एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के संक्षिप्त ब्यौरे से संबंधित रजिस्ट्री आफ कंपनीज एंड बिजनेस (आरसीबी) सिंगापुर से उद्धरण ;
- (ii) स्थायी निवास के लिए निक्षेप स्कीम ;

- (iii) उद्यमी स्कीम के अधीन स्थायी निवास के लिए आवेदन ;
- (iv) स्थायी निवास के लिए निक्षेप स्कीम, प्ररूप 'क' ;
- (v) सिंगापुर में उद्यमियों के लिए स्थायी निवास के लिए आवेदन, प्ररूप 'ख' ; और
- (vi) प्ररूप 4, अप्रवासी अधिनियम-स्थायी निवास के संबंध में प्रवेश अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

5. पूर्वोक्त याचिका में याची द्वारा किए गए अभिकथनों, प्रकथनों और दलीलों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन की विधिमाम्यता के संबंध में, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आक्षेप उन्हीं आधारों पर किए गए थे जिनपर वर्तमान याचिका में किए गए हैं । इसके अतिरिक्त इस याचिका के पैरा 4 (च) में याची ने स्वयं यह कथन किया है कि “श्री दिनाकरन सभी सुसंगत तारीखों को सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्रास्थिति धारित कर रहे थे । जनवरी, 1995 में उनके द्वारा स्थायी निवासी की प्रास्थिति के लिए आवेदन किया गया था और सिंगापुर प्राधिकारियों द्वारा सिंगापुर देश की स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए उसे मंजूर किया गया था । इस निमित्त और इस प्रकार उक्त प्रास्थिति, विधियों (आप्रवास अधिनियम और कंपनी अधिनियम) के अधीन है । सिंगापुर में ऐसी स्थायी प्रास्थिति धारण करके श्री दिनाकरन ने स्पष्ट रूप से किसी विदेशी राज्य की निष्ठा या अनुषक्ति को स्वीकार किया और इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्व से ही उसने संसद् के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हता उपाप्त कर ली थी, जो उसके निर्वाचन के पश्चात् भी बनी हुई है ।” अतः याचिका में उठाया गया अभिकथित निरर्हता का प्रश्न कदाचित् निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है ।

6. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को केवल ऐसी निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता है जिससे कोई आसीन सदस्य, उसके निर्वाचन के पश्चात् ग्रस्त हो जाता है । अतः, अधिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करना निर्वाचन-आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत केवल तभी आता है जब वह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो और निर्वाचन-पश्च निरर्हता से संबंधित हो । निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का कोई भी प्रश्न, अर्थात् ऐसी निरर्हता, जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा ही उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं । इस संबंध में, निर्वाचन आयोग बनाम शाका वेंकट राव (एआईआर 1953 एस.सी. 210) ; बृन्दाबन नाईक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एस.सी.1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एस.सी. 1609), आदि में उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिश्चयों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

7. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित साविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री टी.टी.वी. दिनाकरन की अभिकथित निरर्हता, कदाचित् निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है और इसे संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष न तो उठाया जा सकता है और न ही उनके द्वारा उसका विनिश्चय किया जा सकता है । परिणामस्वरूप,

निर्वाचन आयोग की भी ऐसे अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरहता के संबंध में, राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है।

अतः, मौजूदा याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार चलाए जाने योग्य नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्दिष्ट इस प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने यही मत व्यक्त किया है। इस संदर्भ में, वर्ष 2000 के निर्देश मामले सं० 1,2,3 और 4 में तारीख 13 जुलाई, 2000 की आयोग की राय को देखा जा सकता है, जो समान आधारों पर इसमें वर्तमान प्रत्यर्थी श्री दिनाकरन से ही संबंधित है।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त, याची ने यह भी दलील दी है कि प्रत्यर्थी, जो अनिवासी भारतीय है, भारत में किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं था और इसलिए निर्वाचन नहीं लड़ सकता था। उपरोक्त दलील के संबंध में यह उल्लेख करना उपयुक्त हो सकेगा कि लोकसभा का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होने के लिए किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 84(ग) के अधीन एक 'अर्हता' है, जो संविधान के अनुच्छेद 102(1) में विनिर्दिष्ट 'निरहता' के आधारों में से किसी आधार के अंतर्गत नहीं आती है। इस संबंध में अननुपालन के लिए उपचार कहीं और उपलब्ध है। अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति को कोई याचिका अनुच्छेद 102(1) के अधीन केवल निरहता के प्रश्नों के संबंध में ही होती है, न कि अनुच्छेद 84 के अधीन अर्हताओं के प्रश्नों के संबंध में, जैसा कि अनुच्छेद 103 के उपबंधों से स्वयं स्पष्ट होता है, जो निम्नानुसार है :

'103. सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय - (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।'

अतः, तमिलनाडु में निर्वाचक के रूप में प्रत्यर्थी के रजिस्ट्रीकरण का प्रश्न अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार वर्तमान याचिका में राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता है। वैकटाचलम बनाम स्वामीकेन [(1999) 4 एससीसी 526] के मामले में याची द्वारा जिन आधारों पर भरोसा किया गया है वह सही नहीं है क्योंकि वह मामला अनुच्छेद 226 के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई रिट याचिका से संबंधित है, और अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को दी गई याचिका का या अनुच्छेद 192(2) के अधीन राज्यपाल को दी गई याचिका से संबंधित नहीं है।

9. मौजूदा मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त, इस आशय की राय के साथ कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है, तदनुसार, उन्हें वापस किया जा रहा है।

हस्ताक्षर
(टी.एस.कृष्णमूर्ति)
निर्वाचन आयुक्त

हस्ताक्षर
(जे.एम. लिंगदोह)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

हस्ताक्षर
(बी.बी. टंडन)
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली
11 जुलाई, 2001

[फा.सं. एच-11026(1)/2001-विधायी-2]

एन.एल.मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2001

S.O. 1036 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas Shri Subramanian Swamy, President Janata Party, had submitted a petition dated 23.3.2001 for the disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, a sitting member of Lok Sabha, for being a member of that House on account of his declaring himself as a non-resident Indian in certain proceedings before the court and authorities under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, his holding the permanent resident status in Singapore, being a Director in Adventure Holdings Pvt. Ltd., Dipper Investments Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, registered under the Singapore and United Kingdom laws, which contain provisions relating to rights and duties of a director and provide for penalties for non-compliance of the provisions of their laws and thus being bound by the laws of Singapore and United Kingdom, and which according to him is an acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State, within the

meaning of article 102 (1)(d) of the Constitution and for being registered as an elector in any constituency in India on account of his declaring himself as a non-resident Indian;

And whereas the President had sought the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution, on the question whether Shri T.T.V. Dhinakaran had become subject to disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that in view of the well-settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under article 103(1) of the Constitution. Consequently, the Election Commission has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The question of registration of Shri T.T.V. Dhinakaran as an elector in Tamil Nadu so as to contest election is a qualification under article 84(c) of the Constitution read with section 4 of the Representation of the People Act, 1951 and hence, also can not be raised before, or decided by, the President under article 103(1) of the Constitution. The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of article 103(1) of the Constitution.

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, do hereby decide that the petition of Shri Subramanian Swamy, President, Janata Party, is not maintainable and is therefore rejected.

PRESIDENT”.

19TH September, 2001.

ANNEXURE

CORAM :

Hon'ble Shri T.S. Krishna Murthy Hon'ble Shri J.M. Lyngdoh Hon'ble Shri B.B. Tandon
Election Commissioner Chief Election Commissioner Election Commissioner

Reference Case No. 1 of 2001

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

In re: Alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, a sitting
Member of Parliament (Lok Sabha).

In the matter of :

Shri Subramanian Swamy
President Janata Party,
A-77 Nizamuddin (East),
New Delhi-110013.

Petitioner

Versus

Shri T.T.V. Dhinakaran,
Member of Parliament (Lok Sabha),
S/o Vivekanandan,
24th Street, Venkateswara Nagar,
Adayar,
Chennai-600 020.

Respondent

OPINION

This is a reference, dated 6.6.2001, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri T.T.V. Dhinakaran, a

324661/2001-2

sitting member of the Lok Sabha, has become subject to disqualification, for being a member of that House, under Article 102 (1) (d) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition, dated 23.3.2001, submitted by the above mentioned petitioner to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution of India. In the said petition, the petitioner alleged that Shri T.T.V. Dhinakaran, who contested the election to the Lok Sabha held in September, 1999 from 25-Periyakulam wrongly mentioned in the petition as 75-Periyakulam Parliamentary Constituency in Tamil Nadu, had become subject to disqualification for continuing as a member of the House of the People, for having incurred disqualification under Article 102(1) (d) of the Constitution of India.

3. The petitioner alleged that the respondent, Shri T.T.V. Dhinakaran, declared himself as a non-resident Indian in certain proceedings before the Madras High Court and authorities under the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), and that he secured permanent resident status in Singapore by depositing a sum of One Million Dollars to Singapore Government and also became a Director of a Company, Adventure Holdings Pvt. Ltd. Singapore, and gave his permanent residential address as 37, Jalan Teliti, Singapore. The petitioners further contended that objections to the above effects were also raised before the Returning Officer for 25-Periyakulam Parliamentary Constituency at the time of scrutiny of nomination of the respondent, during the general election to the House of People held in 1999, but the Returning Officer rejected the objections so raised and accepted the nomination paper of the respondent as valid.

4. The petitioner further alleged that the respondent was also a Director in certain other foreign companies, viz., Dipper Investments Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, incorporated under the U.K. laws. The petitioner contended that the respondent by virtue of holding the permanent resident status in Singapore, being a Director in Adventure Holdings Pvt. Ltd., Dipper Investment Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, registered under the Singapore and U.K. laws, which contain provisions relating to rights and duties of a Director and also provide for penalties for non-compliance of the provisions of their laws, is bound by the laws of Singapore and U.K., and as such is under an acknowledgment of allegiance or adherence to a Foreign State, within the meaning of Article 102 (1) (d) of the Constitution, rendering him liable to disqualification for membership of Parliament. In support of the above averments, and contentions, the petitioner has submitted with his petition, Xerox copies of the following documents:-

- (i) Extract from the Registry of Companies and Business (RCB) Singapore regarding the brief details of Adventure Holdings Pvt. Ltd. incorporated on 02.04.1994;
- (ii) Deposit scheme for Permanent Residence;
- (iii) Application for Permanent residence under the Entrepreneur Scheme;
- (iv) Deposit scheme for Permanent Residence, Form 'A';
- (v) Application for Permanent Residence in Singapore for Entrepreneurs, Form 'B'; and
- (vi) Form 4, Immigration Act - application for an Entry Permit for Permanent Residence.

5. From the allegation, averments and contentions made by the petitioner in the aforesaid petition, it is apparent that objections were made before the Returning Officer, at the time of scrutiny of nomination papers, regarding the validity of nomination of the respondent, on the very grounds as have been raised in the present petition. Further, the petitioner himself has stated in Para 4 (f) of the present petition that “ Mr. Dhinakaran on all the relevant dates was holding a permanent resident status at Singapore. The status of permanent residence was applied for by him and granted by the Singapore Authorities in January 1995 subject to local laws of Singapore State. In this behalf and as such, the said status is subject to laws (Immigration Act and Companies Act). By holding such a permanent status in Singapore, Mr. Dhinakaran herein is clearly, under an acknowledgement of allegiance or adherence to a Foreign State thus incurring the disqualification for Membership of either House of Parliament even before the commencement of Election process, and which so continues after his election.” The question of alleged disqualification raised in the petition is, therefore, a case of pre-election disqualification, if at all.

6. It is well settled that under Article 103 (1) of the Constitution, the President has jurisdiction to decide only such question of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his election. Consequently, the jurisdiction of the Election Commission to enquire into question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre-election

disqualification, i.e., disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to, his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Article 329 (b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc.

7. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Article 103 (1) of the Constitution. Consequently, the Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore, non-maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution. The same view has already been expressed by the Commission in a large number of similar cases, referred to it, by the President and Governors of several States. In this context, the opinion dated 13th July, 2000, of the Commission in Reference Cases No.1, 2, 3 and 4 of 2000, which related to the present respondent herein, Shri Dinakaran, himself on similar grounds, may be referred to.

8. Apart from the above, the petitioner has also contended that the respondent, being a non-resident Indian, was not entitled to be registered

as an elector in any constituency in India, and thus could not contest the election. In regard to the above contention, it may be pertinent to point out that to be an elector in a Parliamentary Constituency so as to be eligible to contest an election to the House of the People is a 'qualification' under Article 84 (C) of the Constitution read with section 4 of the Representation of the People Act, 1951, and is not covered under any of the grounds of 'disqualification' specified in Article 102(1) of the Constitution. The remedy for non-compliance in this regard lies elsewhere. A petition to the President, in terms of Article 103(1), lies only in relation to questions of disqualification under Article 102(1), and not in relation to questions of qualifications under Article 84, as is self-evident from the provisions of Article 103, which reads as under:

'103. Decision on question as to disqualifications of members. (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

Thus, the question of registration of the respondent as an elector in Tamil Nadu cannot be raised in the present petition before the President in terms of Article 103(1). The reliance put by the petitioner on the case of Venkatachalem Vs Swamickan (1999) 4 SCC 526) is misplaced, as that related to a writ petition entertained by the Madras High Court under

Article 226, and not to a petition to the President under Article 103(1) (or to a petition to the Governor under Article 192 (2)).

9. The reference received from the President, in the present case, is accordingly returned to him, with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Sd/-
(T.S. Krishna Murthy)
Election Commissioner

Sd/-
(J.M. Lyngdoh)
Chief Election Commissioner

Sd/-
(B.B. Tandon)
Election Commissioner

New Delhi
Dated : 11th July, 2001

[F. No. H-11026(1)/2001-Leg. II]
N. L. MEENA, Jt. Secy. and Legislative Counsel

